भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5712** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/ 14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

सामरिक महत्व के मेगा-पत्तनों का विकास

†5712. श्री नरेश गणपत म्हस्के :

श्री राजेश वर्मा :
श्रीमती शांभवी :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2047 तक भारत की पत्तन क्षमता को बढ़ाकर 10,000 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की सरकार की पहल किस प्रकार देश के आर्थिक पुनरुत्थान में सहायक हो सकती है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं कि वधावन जैसे सामरिक महत्व के मेगा-पत्तनों और गलाथिया खाड़ी के विकास से वैश्विक पोत परिवहन केन्द्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो;

(ग) क्या कंटेनर के ठहराव समय और जलयान के टर्नअराउंड समय में कमी से पत्तन के दक्षता में सुधार करने मामले में सरकार की नीतियों की सफलता का पता चलता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें और सुधार करने की योजना क्या है;

(घ) प्रमुख पत्तनों पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने से समुद्री क्षेत्र में निवेश और रोजगार सृजन को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की उम्मीद है; और

(ङ) पोत निर्माण में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता और सतत् ईंधन को अपनाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं और ये प्रयास किस प्रकार से भारत के वैश्विक रूप से अग्रणी बनने की महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): 2047 तक पत्तन क्षमता को 10,000 मिलियन टन तक बढ़ाने की सरकार की पहल का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके और पोत के टर्नअराउंड समय को कम करके व्यापार दक्षता को बढ़ाना है। यह विस्तार कार्गो हैंडलिंग को तेजी से, अधिक लागत प्रभावी तरीके से सक्षम करके भारत के वैश्विक निर्यात को सुदृढ़ करेगा तथा और अधिक ठोस व्यापार अवसंरचना के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक विकास का संवर्धन करेगा।

(ख): सरकार, बड़े जलयानों के लिए जगह बनाने के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वधावन जैसे मेगा पत्तनों का विकास कर रही है। इसके अतिरिक्त, गलाथिया बे एक कार्यनीतिक पत्तन बनने के लिए तैयार है, जिससे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्कता बढ़ेगी। ये पहल वैश्विक शिपिंग हब में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए हैं।

(ग): भारतीय पत्तनों पर कंटेनर जलयानों का टर्नअराउंड समय वित्त वर्ष 13-14 में 42 घंटों से घटकर वित्त वर्ष 23-24 में 30 घंटे होना पत्तन दक्षता में सुधार लाने में सरकारी नीतियों की सफलता को दर्शाता है। भविष्य में, स्वचालन, पत्तन विस्तार, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एआई और आईओटी) का एकीकरण इन लाभों को बनाए रखने और भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को मजबूत करने के लिए जरूरी होगा।

(घ): राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में सहायता देने के लिए भारत में तीन महापत्तनों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इन पहलों से इलेक्ट्रोलाइज़र, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और भंडारण सुविधाओं में उल्लेखनीय निवेश होगा। परिणामस्वरूप, ये पतन कुशल कामगारों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करेंगे और उपस्कर निर्माण और लॉजिस्टिक्स में अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेंगे।

(ङ): कुशल श्रम चुनौतियों से निपटने करने के लिए, सरकार ने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में बी.टेक. कार्यक्रम जैसी पहल शुरू की और समुद्री और पोत निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय वैकल्पिक ईंधन में अनुसंधान और विकास में सहायता करता है, जबकि कोचीन शिपयार्ड पर्यावरण के अनुकूल जलयानों को बढ़ावा देते हुए हरित पोत निर्माण में अग्रणी है।

*****